सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया एक गैर-सरकारी संगठन है, जो सरकार के नियंत्रण में नहीं है । इसलिये प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया और तास के बीच समाचारों के विनिमय का प्रश्न उन दोनों में आपस की बातचीत से ही तै होना चाहिये । अतः प्रत्यक्षतः सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता । पर सरकार समाचारों को लेने देने के लिए भारतीय और विदेशी समाचार एजेन्सियों के बीच व्यवस्था का सामान्यतः स्वागत करती है ताकि अधिकाधिक भारतीय समाचार विदेशों में जाएं, और विदेशी समाचार भारत में मिलें ।

पता चला है कि तास एजेन्सी ने प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया से प्रस्ताव किया है कि वे एक दूसरे के समाचार रेडियो पर सुन कर लिया करें । परन्तु जहां तक हमें मालूम है, अंतिम रूप से कोई फ़ैसला नहीं हुआ है ।

प्रेस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया

1056. **श्री मधु लिमये :**
श्री रामसेवक यादव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रैस ट्रस्ट आफ़ इण्डिया को केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितनी सहायता दी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : प्रैस ट्रस्ट आफ़ इंडिया को सहायता के रूप में रुपया नहीं दिया जाता । पत्र सूचना कार्यालय इसे स्वीकृति देता है और समाचार लेने की अन्य सुविधाएं देता है । देश विदेश के समाचारों को एकत्र करने और देने के लिए डाक तार विभाग ने इन वे-तार और टेली प्रिंटर लाइन जैसी कुछ विशेष संचार सुविधाएं दी हैं । आकाशवाणी और पत्र सूचना कार्यालय प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया से निर्धारित दर पर खबरें लेते हैं ।

1965–66 में दी जाने वाली राशि इस प्रकार है :—

आकाशवाणी—11.34 लाख रुपये

पत्र सूचना कार्यालय—12,000 रुपये (टेलीप्रिंटर मशीन के किराए सहित)

इनके अतिरिक्त, विदेश मंत्रालय आदि कुछ मंत्रालय भी प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया से खबरें लेते हैं ।

पार्लियामेंट स्ट्रीट में अपनी जमीन पर इमारत बनाने के लिए ऋण के वास्ते प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया की प्रार्थना पर सरकार विचार कर रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति आयोग के अधीन अणु शक्ति केन्द्र

1057. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री मधु लिमये :
श्री व० बा० गांधी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंडवेल केन्द्र के सम्बन्ध में ब्रिटेन की पेशकश सम्बन्धी समाचारों के पश्चात् भारत सरकार को ब्रिटेन अथवा किसी अन्य देश ने सुझाव भेजा है कि भारत को अपने अणु शक्ति केन्द्रों को अन्तर्राष्ट्रीय अणु शक्ति आयोग के अधीन कर देना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) ब्रिटेन अथवा किसी अन्य देश द्वारा भारत सरकार को ऐसा कोई सुझाव नहीं भेजा गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।